PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 5, ISSUE 5

ग्रामीण विकास में कौशल विकास की भूमिका एवं अपेक्षाओं का अवलोकनार्थ अध्ययन

डॉ. आर. एच. नगरकर
सहयोगी प्राध्यापक
जी. एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स
नागपूर (महाराष्ट्र) भारत

सारांश :–

देश में विशेषत: युवा वर्ग के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाय तो ग्रामीण विकास साधा जा सकता है। भारत सरकार का केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इस हेतू विशेष प्रयास कर रहा है कौशल विकास की अनेक गतिविधियॉं, कार्यक्रम और योजनाए को अंमल में लाया जा रहा है। केन्द्रीय बजट में इसके लिए बडी धनराशी का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास से लाभान्वित ग्रामीण क्षेत्र के युवा को रोजगार सुधार होगा तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी ग्रामीण विकास में कौशल विकास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रस्तावना :

ग्रामीण विकास ही राष्ट्र की प्रगति का आधार हो सकता। ग्रामों की संपन्नता और समृद्धता ही देश की अर्थव्यवस्था को सही मायने में सशक्त बना सकती है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा हिस्सा है जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहना उचित होगा। देश की GDP में ग्रामीण भागों का बड़ा योगदान होता है। ग्रामीण विकास के लिए गावों में रोजगार सृजन करने के लिए स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। देश की बेरोजगारी की अवस्था चिंताजनक हैं। बेरोजगारी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रो से संबंधित है। कुशल श्रमिक अर्थात श्रमशक्ति है जिसे मानव संसाधन कहते है। ग्रामीण युवावर्ग को कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए सरकारी प्रयासों का अवलोकन आवश्यक है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। बड़ी संख्या में उपलब्ध युवावर्ग को रोजगार की दृष्टि से कुशल बनाना, प्रशिक्षित करना, उनमें उद्यमिता विकसित करना प्रत्येक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य कौशल विकास योजना का अध्ययन करना है जिससे भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों में वृद्धि हो सके कौशल से आशय, ऐसा ज्ञान और क्षमता से है जो किसी कार्य को करने में विशेषत: प्रदान करती है।

रोजगार प्राप्ती में कुशलता आवश्यक है। कौशल विकास से आशय, व्यक्ति में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट निपुणता, योग्यता एवं क्षमता को विकसित करने के लिए ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है।

योजना आयोग के अनुसार ऐसा भौगोलिक भाग जहां की जनसंख्या १५००० से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते है। नॅशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाईजेशन के अनुसार ग्रामीण भाग वह है १) जहॉ की जनसंख्या ४०० वर्ग किलोमीटर में बसी हो, २) उस भाग की सीमा निश्चित हो, ३) जहां की कम से कम ७५ प्रतिशत पुरूष जनसंख्या कृषी कार्यो में संलग्नित हो।

सरकारी योजना और उसकी आवश्यकता :

वर्तमान केन्दीय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कौशल भारत, कौशल भारत के उद्देश्य है–

१. कौशल विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण करना।

२. व्यावसायिक कुशलता तथा रोजगार अनुकुल प्रशिक्षण देना।

३. कुशल मानव संसाधन (श्रमशक्ति) का निर्माण करना।

सरकार का केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास कार्यक्रम और कुशल भारत अभियान के लिए उत्तरदायी है।

इस योजना की अपेक्षा है, युवावर्ग की शक्ति और कौशल का उपयोग केवल स्थानीय और राष्ट्रीय श्रम बाजार तक ही सीमित ना हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में भी उनकी मांग हो जिसके लिए उनमें योग्यता, क्षमता एवं कुशलता का विकास करना आवश्यक है। भारत कुशलता की राजधानी बने, ग्रामीण विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार प्रयत्नशील है। कौशल विकास योजना और कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण भागों में काफी संभावनाए और क्षमताए है। ग्रामीण क्षेत्रो से निर्यात में वृद्धि की जा सकता है। निर्यातीत वस्तुओं के निर्माण में इस योजना और कार्यक्रमों से कौशल विकास होगा। विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तकला, कुटीर उद्योग, हस्तोद्योग, कपडा निर्माण, पेड़ पौधो से औषधि निर्माण आदि का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किया जा सकता है।

इसके लिए किए गये प्रयत्न यशस्वी होते दिखायी दे रहे है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रोजगार निर्माण होगा, जिसके लिए कौशल विकास पूरक सिद्ध होगा। भारत सरकार ने रोजगार सृजन के लिए विदेशी कंपनियो के आगमन को आकर्षित करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों और प्रावधानों को उदार बनाया हे। इससे देश में कुशल श्रम शक्ति का उपयोग बढेगा उनकी आय में वृद्धि होगी जो देश की GDP बढ़ाने मे सहायक होगी।

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का प्रतिशत ५ से अधिक है। बढती बेरोजगारी गंभीर समस्या की चेतावनी दे रही है। विश्व के सबसे युवा देश जहाँ दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की संख्या हो वहां उनको रोजगार ना मिल पाना युवाशक्ति एवं क्षमता का व्यय होना है, युवावर्ग की अधिक आबादी जहां देश के लिए वरदान है वही इनका उपयोग नही होने पर यह देश के लिए अभिशाप बन जायेगी, इस दृष्टि से कौशल भारत योजना अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी सिद्ध होगी। अब इसकी सफलता और यश के लिए सरकारी गैरसरकारी प्रयत्नों की अत्यंत आवश्यकता है।

कौशल विकास और बजट :

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का बजट वर्ष २०१७–१८ में विगत बजट से २.५ गुना अधिक राशी खर्च करके १७,००० करोड रू. रहा। वर्ष २०१८–१९ में २८२० करोड रू. था, वर्तमान वर्ष २०१९–२० में यह बढ़ाकर २९८९ करोड रू. किया गया है। बजट से संबंधित कौशल विकास के सरकारी प्रयास इस प्रकार है–

१. प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (PMKK) का वर्तमान में ६० जिल्हों में संचालन हो रहा है जिसे ६०० जिल्हों में आरंभ करने की योजना है।
२. देश में १०० भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्र आरंभ करना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देना तथा विदेशी भाषा सिखाने की व्यवस्था करना।
३. संकल्प (SANKALP - Skill Acquisition and Knowledge Awarness for Livelihood Promotion Programme) आरंभ करना जिसके लिए ४००० करोड रू. व्यय किए जायेंगे। जिसमें बाजार संबंधित अनुकूल प्रशिक्षण देना जिससे ३.५ करोड युवाओं को लाभान्वित करना।
४. औद्योगिक मूल्य विस्तार के लिए कौशल सशक्तिकरण STRIVE (Skill straightening for Industrial Value Enhancement) का दुसरा चरण लागू करना जिसके लिए २२०० करोड रू. की लागत होगी। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) द्वारा गुणवत्ता वृद्धि एवं बाजार प्रासंगिकता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। इससे युवा वर्ग की कुशलता में वृद्धि होगी और उद्योगों को कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध होगी।
५. चमड़ा, जूते चप्पल तथा कपड़ा उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनायी है। कपड़ा उद्योग का देश में रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र (कृषी क्षेत्र के पश्चात) है जहां ३३–३५ मिलीयन लोगो को रोजगार प्राप्त हो रहा है जिसे इस योजना के तहत २०२२ तक बढ़ाकर ६०–६२ ग्रामीण मीलियन रोजगार मूहैया कराने का लक्ष्य है।
६. ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के प्रसार के लिए ४५०० करोड रू. का आवंटन किया है।

७. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP (PM's employment generation Programme) के बजट में ३ गुना अधिक राशी का प्रावधान करना, जिससे कुशल मानव संसाधन का उपयोग किया जा सके।

८. ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए मिस्त्री–कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ५ लाख लोगो को वर्ष २०२२ तक प्रशिक्षण देना।

९. तकनीकी विकास करना जिससे नए युवावर्ग को नए स्टार्टअप करने में सहायता करना।

१०. अति वेगवान ब्रॉडबैंड की सुविधा १.५ लाख गावों तक पहुचाना।

इसके अलावा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आजिविका योजना है, जो कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने में पहल कर रही है। जिसका उद्देश्य है, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के युवाओं को विशिष्ट ज्ञान और कौशल प्रदान करना जो उन्हें शीघ्र रोजगार दे सके। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने १५०० करोड रूपये का प्रतिवर्ष प्रावधान NRLM (Nation Rural Livelihood Mission) में किया है जिससे गरीबी की रेखा के नीचे युवाओं में कुशलता के विभिन्न प्रशिक्षण दिया जायेगा। कुल ७३ कौशल विकास की योजनाएँ भारत सरकार के २० मंत्रालयों द्वारा अंमल में लायी जा रही है।

समस्याएँ :

१. **कुशल मानव संसाधन का अभाव** : जहां निर्माण कार्य शुरू है वहां कुशल बढ़ई, वेल्डर इलेक्ट्रीशियन का अभाव है, विभिन्न औद्योगिक, ईकाईयों में जैसे गोदाम और लॉजिस्टिक फेब्रीकेशन आदि में कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या कम है।

२. **कार्यसंस्कृति का अभाव** : विभिन्न औद्योगिक इकाईयां अपने मानव संसाधनों से जिस प्रकार की कार्य संस्कृति (Work Cultural) की अपेक्षा रखती है, वह उन्हें श्रमिकों में दिखायी नही देती है।

३. **आकर्षक औद्योगिक नीति का अभाव** : कुशल मानव संसाधनों को उद्योग ही रोजगार देते है, किंतु उद्यमी और प्रबंधक यह महसूस करते है कि जिले के लिए औद्योगिक नीति अपनी मित्रतापूर्ण और अनुकूल अथवा प्रोत्साहनपूरक नही है।

४. **उचित पारिश्रमिक का अभाव** : कुशल श्रमशक्ति के लिए पारिश्रमिक कम होने की शिकायते कुशल श्रमिक करते दिखायी देते है।

५. **काम देनेवाले और काम माँगनेवाले के बीच कड़ी का अभाव** : कुशल मानव संसाधन एवं औद्योगिक ईकाई को जोड़ने वाली रोजगार विनिमय कार्यालय (Employment Exchange Centre) पूर्णत: सूस्त है।

रोजगार निर्माण करनेवाले अन्य विभिन्न क्षेत्र वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, खाद्य संस्करण, सूचना व तकनीकी (IT), रेडिमेड कपडे, हॉस्पिटीलिटी, संचार माध्यम, मिडीया, यातायात आदि जिले में कार्यरत है, जहॉ कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकार की समस्याएँ संपूर्ण देश में व्याप्त है।

सुझाव :

१. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषी व अकृषी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर निर्माण किए जाने चाहिए।
२. अधिकाधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना चाहिए।
३. कुशल एवं प्रशिक्षित लोगों के वास्तविक आंकडों की जानकारी मंत्रालय में होनी चाहिए।
४. कौशल केन्द्रों की गतिविधियों की अधिकतम प्रभावी बनना चाहिए।
५. सरकारी बजट का ईमानदारी से उपयोग एवं पूरा व्यय किया जाना चाहिए।
६. युवा वर्ग को कौशल विकास के आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
७. विशेषत: आधुनिक तकनीकी जानकारी एवं उसका उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाये।
८. नीजि उद्यमीयों को प्रत्येक जिल्हों में उद्यम एवं व्यावसायिक ईकाईयॉ स्थापित करने के लिए सरकारी सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए।
९. लैगिक समानता के सिद्धांत के अनुसार युवतियों एवं महिलाओं को कौशल विकास के अवसर अधिक प्रदान किए जाये।
१०. शालेय स्तर पर कौशल आधारित बेसीक अभ्यासक्रम से संबंधित शिक्षा तथा विषयों में इसे शामिल किया जाये।
११. प्रशिक्षण पारंगतो को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए।
१२. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाई आरंभ करनेवाले उद्यमियों के लिए कडे सरकारी नियम व प्रावधानों को उदार बनाना चाहिए।
१३. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होनेवाले उद्यमों में स्थानीय युवावर्ग को नौकरियों में प्राथमिकता एवं अधिक स्थान देने चाहिए।
१४. कौशल विकास प्रशिक्षणार्थियों को सरकार द्वारा स्कॉलरशीप/स्टायफंड देना चाहिए।
१५. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण का महत्व संबंधि जानकारी दी जाये।
१६. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल और संसाधनों का उपयोग के तरीकों की जानकारी दी जाये।
१७. कौशल विकास प्राप्त व्यक्तियों को उसके काम का उचित पारिश्रमिक दिया जाये।
१८. कुशल व्यक्ति द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध करना एवं उचित प्रदान किया जाए।
१९. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों द्वारा कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए बनायी गयी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में समन्वयक भूमिका निभाकर समन्वय स्थापित करना चाहिए।
२०. कुशल व्यक्ति द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए देशभर में विक्रय की व्यवस्था निर्माण हो।

२१. वस्तुए निर्यात करने के लिए सरकारी एजंसिने मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहिए।

निष्कर्ष :

कौशल विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए विशेष मंत्रालय बनाया गया है। बजट में हर वर्ष बड़ी धन राशी का प्रावधान किया गया है। युवा भारत को रोजगार निभाने में कौशल विकास ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सकता है। सरकार केंन्द्र ग्रामीण विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में गति लाने के साथ नीजि व्यावसायिक संस्थाओं के प्रयासो की भी आवश्यकता हे। कौशल विकास और उद्यमिता में एकात्मकता लाने की सरकार का प्रयत्न प्रशंसनीय है। किंतू वास्तविक रूप में इस योजना को लागू करने की राह में देश की परंपरागत सोच, अधिकारियों की उदासीनता, भ्रष्टाचार केवल विज्ञापन की अधिकता, बडी बाधा है, अन्यथा यह योजना का सफल होना युवाशक्ती का शानदार उपयोग होगा जो युवावर्ग को क्षमतावान, सामर्थ्यवान बनाने के साथ उन्हें जिविकापार्जन का साधन उपलब्ध करायेगा। जो देश की आय वृद्वि में प्रमुख साधन बनेगा।

संदर्भ :

1) The Apprentices Act, 1961, Available: http://mhrd.gov.in/sites/upload_ files/mhrd/files/upload_doc ument/ApprenticeAct1961.pdf
2) www.indiabudget.nic.in,Available:http://indiabudQet.nic.in/ub2017-1filbhibh1.pdf
3) Census 2001, Available: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/ India_at_ glance/rural.aspx
4) In Focus: India, where is it? Dec 2010, Available:http://www.dhanbank.com/pdf/reports/InFocus December%201,%202010.pdf
5) Census 2011, Available: http://www.censusindia.gov.in/2011- common/census_ 2011.html
6) Twelfth Five Year Plan, Planning Commission, Government of India, Volume 1 - Volume 3, 2013.
7) World Bank Report, Available: http://siteresources.worldbank.org/ ESSDNETWORK JReso urces/ Roadto2050Partl.pdf
8) FICCI-KPMG report, "Re-engineering the skill ecosystem", Available: http://ficci inispd.ocumen t/20762/Re-engineering-the-skit I ecosystem.pdf.
9) https:/insdcindia.orgisitesidefault/files/filesimaha-sg-reports .pdf